[2014] 7 एस. सी. आर 1123

अशरफ कोक्कुर

बनाम

के. वी. अब्दुल खादर आदि

(सिविल अपील संख्या 69-70 /2012)

अगस्त 29, 2014

[न्यायाधिपति मदन बी. लोकुर और न्यायाधिपति कुरियन जोसेफ]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 7, नियम 11 (ए) – कार्यवाही का कारण - चुनाव याचिका - राज्य विधान सभा में लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती - अयोग्यता के आधार पर क्योंकि वह लाभ का पद धारण कर रहा था, अर्थात केरल राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष - उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज कर दी गई यह मानते हुए कि इसने कार्यवाही के पूर्ण कारण या समाधान योग्य मुद्दे का खुलासा नहीं किया- माना गया: आदेश 7, नियम 11(ए) के तहत जांच केवल इस बात के लिए है कि क्या जैसा कि दलील दी गई है, तथ्य कार्यवाही के कारण का खुलासा करते हैं न कि कार्यवाही के पूर्ण कारण का - सीमित जांच केवल यह देखने के लिए है कि क्या याचिका को दहलीज पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए - भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद धारण करना क्या अयोग्यता है - यदि चुनाव याचिका को समग्र रूप से पढ़ा जाता है तो वह आधार स्पष्ट है या नहीं, यह उच्च न्यायालय द्वारा किया जाने वाला सरल कार्य है जब उसे आदेश 7, नियम 11(ए) के तहत ऐसा करने के लिए कहा जाता है - वर्तमान मामले में, दिए गए कथन चुनाव याचिका में कार्यवाही के कारण का स्पष्ट

रूप से खुलासा करें, अर्थात प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर था और केरल सरकार से वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहा था और इस प्रकार, केरल राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने के कारण भारत के संविधान की धारा 191(1)(ए) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। - यह चुनाव याचिका में विचारणीय मुद्दा है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 83 - चुनाव याचिका - भौतिक तथ्य - लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अयोग्यता के आधार पर चुनौती दी गई क्योंकि वह लाभ का पद धारण कर रहा था - उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें यह दलील नहीं थी कि प्रतिवादी राज्य के तहत लाभ का पद धारण कर रहा था। सरकार - माना गया: धारा 83(1)(ए) के तहत धारा 83(1)(बी) के विपरीत आवश्यकता यह है कि चुनाव याचिका में केवल भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, न कि भौतिक विवरण - अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य' का स्पष्ट अर्थ है विषय वस्तु से संबंधित तथ्य और जिन पर चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया जाता है - यदि पार्टी उन तथ्यों को साबित नहीं करती है, तो वह परीक्षण में विफल हो जाती है - तत्काल मामले में, दलीलें, (जैसा कि चुनाव में निहित है) याचिका और अनुलग्नक पी1 (डी), जो चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग है) को यदि समग्र रूप से लिया जाए, तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वे सामग्री का गठन करते हैं तथ्य ताकि एक विचारणीय मुद्दा उठाया जा सके कि क्या प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए केरल राज्य विधान सभा में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है - एक चुनाव याचिका में, आवश्यकता यूएलएस 83 है भौतिक तथ्यों का सटीक और संक्षिप्त विवरण प्रदान करें - अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य' का स्पष्ट अर्थ है विषय वस्तु से संबंधित तथ्य और जिन पर चुनाव द्वारा भरोसा किया जाता है याचिकाकर्ता - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 191.

धारा 83 - चुनाव याचिका - उसके अनुलग्नक - माना गया: वर्तमान मामले में, वर्तमान मामले में चुनाव याचिका से जुड़े सभी अनुलग्नकों पर धारा 83(2) के तहत आवश्यकता के अनुसार चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया गया है - इसलिए, चुनाव याचिका का अनुलग्नक-पी1(डी) चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग है - एक स्पष्ट और स्पष्ट दलील है कि प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाल रहा था, जो केरल सरकार के अधीन लाभ का पद है और, ऐसे में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

जब प्रतिवादी ने केरल विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वह केरल राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था। चुनाव याचिका के अनुबंध पी1 (डी) के अनुसार, अपीलकर्ता ने उनके नामांकन पर आपत्ति जताई। हालाँकि, दिनांक 29.03.2011 के आदेश के अनुसार, आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। अंततः प्रतिवादी चुना गया। अपीलकर्ता ने एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें अयोग्यता के आधार पर प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती दी गई क्योंकि वह लाभ का पद यानी केरल राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था। उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कार्रवाई का पूरा कारण या विचारणीय मुद्दे का खुलासा नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चुनाव याचिका में स्पष्ट रूप से यह दलील नहीं थी कि प्रतिवादी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद रखता है। दलील केवल इस आशय की है कि प्रतिवादी लाभ का पद रखता है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. सीपीसी की धारा आदेश 7, नियम 11(ए) के तहत जांच केवल इस बात के लिए है कि क्या बताए गए तथ्य कार्यवाही के कारण का खुलासा करते हैं, न कि कार्यवाही के पूरे कारण का। सीमित जांच केवल यह देखने के लिए है कि क्या याचिका को दहलीज पर ही फेंक दिया जाना चाहिए। एक चुनाव याचिका में, आरपी अधिनियम

की धारा 83 के तहत आवश्यक तथ्यों का सटीक और संक्षिप्त विवरण प्रदान करना है। अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य' का स्पष्ट अर्थ है विषय वस्तु से संबंधित तथ्य और जिन पर चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया जाता है। यदि पक्ष उन तथ्यों को साबित नहीं करता है, तो वह मुकदमे में विफल हो जाता है। [पैरा 25] [1143-डी-एफ]

1.2. हरि शंकर जैन के मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अभिव्यक्ति कार्यवाही का कारण' का अर्थ अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए तथ्यों को साबित करना होगा, यदि इसका पता लगाया जाए। पार्टी को ऐसी अतिरिक्त जानकारी के साथ कार्यवाही के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करनी होगी ताकि विपरीत पक्ष को उस मामले के बारे में समझ आ सके जिससे उसे मिलना होगा। [पैरा 29) [1145-बी-सी]

हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी 2001 (3) सप्ल एससीआर 38 = (2001) 8 एससीसी 233 - पर निर्भर

सैयद दस्तगीर बनाम टी.आर. गोपालकृष्ण सेट्टी 1999 (1) सप्ल एससीआर 351 = 1999 (6) सेकंड 337 आई मेयर (एच.के.) लिमिटेड बनाम मालिक और पार्टियाँ, वेसल एम.वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस 2006(1) एससीआर 860 = 2006 (3) एससीसी 100; पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और अन्य 2012 (6) एससीआर 851= 2012(7) एससीसी 788, राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी और अन्य 1972 (3) एससीआर 841 = 1972 (3) एससीसी 850 - संदर्भित।

1.3. मौजूदा मामले में, आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद रखता है और उस क्षमता में वह केरल सरकार से उस कार्यालय से जुड़े मुनाफे का आनंद लेता है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना अयोग्यता है। यदि चुनाव याचिका को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो वह आधार समझ में आता है या नहीं, यह सरल प्रक्रिया है

जिसे उच्च न्यायालय द्वारा तब किया जाना चाहिए जब उसे सीपीसी के आदेश 7, नियम 11(ए) के तहत चुनाव याचिका के पैराग्राफ-3 के तहत ऐसा करने के लिए कहा जाए। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अर्थात लाभ के पद पर था। फिर से उसी पैराग्राफ में यह कहा गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसा पारिश्रमिक मिलता है जो केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और निर्धारित किया जाता है। संविधान की अनुच्छेद 191 को उद्धृत करने के बाद यह अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत लाभ का पद रखता है। राज्य सरकार को विधान सभा का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। यह फिर से दलील दी गई है कि केरल राज्य ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की अयोग्यता को हटाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष संविधान की अनिच्छेद 191 के तहत अयोग्य हैं। पैराग्राफ-6 में, विवरणों की गणना करते हुए, यह दलील दी गई है कि प्रतिवादी लाभ का पद धारण कर रहा था, उसे मानदेय, भत्ते दिए गए थे और राज्य के खर्च पर कार की सुविधा का आनंद ले रहा था और अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था। फिर से, नीचे

पैराग्राफ-7 में कहा गया है कि प्रतिवादी को ड्राइवर उपलब्ध कराया गया था, जिसके वेतन और भत्ते का भुगतान भी केरल सरकार के कोष से किया जाता है। पैराग्राफ-10 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "चूंकि चुनाव की तारीख पर, पहला प्रतिवादी केरल राज्य वक्फबोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद संभाल रहा था, इसलिए उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था"। ये कथन स्पष्ट रूप से कार्रवाई के कारण का खुलासा करते हैं जैसे कि प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद संभाल रहा था और केरल सरकार से वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहा था और इस तरह कला के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। भारत के संविधान की अनुच्छेद 191 (1)(ए), केरल राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के रूप

में। यह चुनाव याचिका में विचारणीय मुद्दा है। [पैरा 15 और 26) [1136-एफ-एच; 1137-ए-एच]

1.4. आरपी अधिनियम की धारा 83(1)(बी) के विपरीत आरपी अधिनियम की धारा 83(1)(ए) के तहत आवश्यकता यह है कि चुनाव याचिका में केवल भौतिक रणनीति का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, न कि भौतिक विवरण. वी.एस. अच्युतानंदन के मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह विचार किया है कि केवल इसलिए कि पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है, एक चुनाव याचिकाकर्ता को दहलीज से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 14 और 27) [1136-डी; एफ 1144-बी-सी]

वी. एस. अच्युतानंदन बनाम पी. जे. फ्रांसिस और अन्य 1999 (2) एससीआर 99 = 1999 (3) एससीसी 737- संदर्भित।

1.5. वर्तमान मामले में चुनाव याचिका से जुड़े सभी अनुबंधों पर आरपी अधिनियम की धारा 83(2) के तहत आवश्यकता के अनुसार चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया गया है। इसलिए, चुनाव याचिका का अनुलग्नक-पी1(डी) चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग है। एक स्पष्ट और स्पष्ट दलील है कि प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड का पद संभाल रहा था, केरल सरकार के तहत लाभ का पद संभाल रहा था और इस तरह, वह अयोग्य था। [पैरा 19] [1140-एच; 1141-ए-बी]

जी.एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्न कुमार 2013 (4)एससीआर 1107 = (2013) 4 एससीसी 776; और एम. कमलम बनाम डॉ. वी.ए. सैयद मोहम्मद 1978 (3) एससीआर 446 = (1978)2 एससीसी 659 -पर भरोसा किया गया।

सहोदराबाई राय बनाम राम सिंह अहरवार 1968 एससीआर 13 =एआईआर 1968 एससी 1079 - संदर्भित।

1.6. दलीलें, (जैसा कि चुनाव याचिका और अनुलग्नक पी 1 (डी) में निहित है, जो चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग है) अगर समग्र रूप से लिया जाए, तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वे भौतिक तथ्यों का गठन करते हैं ताकि एक विचारणीय मुद्दा खड़ा हो सके कि क्या पहले प्रतिवादी को केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर रहते हुए केरल राज्य विधान सभा में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। [पैरा 23] [1143-ए-बी]

1.7. सवाल यह नहीं है कि केरल राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष लाभ का पद है या नहीं, यह मुद्दा है जिस पर सुनवाई होनी है। सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में ऐसा कोई सवाल उठाया है. भारत के संविधान के तहत अयोग्यता, राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना है। याचिकाकर्ता ने उस संबंध में सभी भौतिक विवरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, याचिका कार्यवाही के कारण का खुलासा करती है। [पैरा 24] [1143-बी-डी]

मोहन रावले बनाम दामोदर तात्याबा उर्फ दादासाहेब और अन्य 1992 (3) पूरक एससीआर 850 =1994 (2) एससीसी 392 - पर निर्भर।

अज़हर हुसैन बनाम राजीव गांधी 1986 एससीआर 782 =1986 पूरक एससीसी 315 - संदर्भित।

फिलिप्स बनाम फिलिप्स और अन्य (1878) 4 क्यूबीडी 127, 133 - संदर्भित।

1.8. इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि चुनाव याचिका में कार्रवाई के कारण का खुलासा किया गया है, इसलिए इसे दहलीज पर नहीं फेंका जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश एवं निर्णय को निरस्त किया जाता है। चुनाव याचिका कानून के अनुसार सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को भेजी जाती है। [पैरा 34] [1148-8-सी]

वाद कानून संदर्भित

1968 एस सी आर 13	संदर्भित	पैरा 16
1978(3)एस सी आर 446	संदर्भित	पैरा 18
2013(4) एस सी आर	संदर्भित	पैरा 21
(1878)4 क्यूबीडी 127.133	संदर्भित	पैरा 25
1992(3)पूरक एस सी आर 850	संदर्भित	पैरा 25
1986 एस सी आर 782	संदर्भित	पैरा 26
1999(2)एस सी आर 99	संदर्भित	पैरा 27
2001(3)पूरक एस सी आर 38	संदर्भित	पैरा 29
1999(1)पूरक एस सी आर 351	संदर्भित	पैरा 30
2006(1)एस सी आर 860	संदर्भित	पैरा 31
2012 (6)एस सी आर 851	संदर्भित	पैरा 32
1972 (3) एस सी आर 841	संदर्भित	पैरा 33

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 69-70/2012

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय की 2011 की चुनाव याचिका संख्या 2 में 2011 के आईए संख्या 4 में निर्णय और आदेश 16.11.2011 से।

अपीलकर्ता की ओर से आर. बसंत ई.एम.एस. अनम।

राजीव धवन, वी.के. वर्मा, वी.के. बीजू, विजय लक्ष्मी प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

न्यायाधिपति कुरियन

1. इस मामले में विचार के लिए उठने वाला सरल प्रश्न यह है कि क्या चुनाव याचिका में दिए गए कथन नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 (ए) के तहत अपेक्षित कार्यवाही के कारण का खुलासा करते हैं (इसके बाद इसे कहा जाएगा 'सीपीसी')। संयोग से, यह ध्यान दिया जा सकता है कि चुनाव याचिका दिनांक 16.11.2011 के आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई है, जो इस प्रकार है

"निर्णय

आई ए 4/11 की अनुमति है. चुनाव याचिका को तुरंत खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यह कार्रवाई का पूरा कारण या विचारणीय मुद्दे का खुलासा नहीं करता है।"

बेशक, आई ए 4/2011 के आदेश दिनांक 16.11.2011 में विस्तृत कारण दिए गए हैं, जो एक अपील में चुनौती के अधीन भी है।

2. चुनाव में एकमात्र आधार. याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ए) के तहत अयोग्य है, क्योंकि वह केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाल रहा था। जहां तक प्रासंगिक है, अनुच्छेद इस प्रकार है:

"191. सदस्यता के लिए अयोग्यता.-(1) xxx

(ए) यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद रखता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा घोषित पद के अलावा इसके धारक को अयोग्य नहीं ठहराता है;"(जोर दिया गया)

3. उच्च न्यायालय का मानना है कि चुनाव याचिका में स्पष्ट रूप से यह दलील नहीं दी गई है कि प्रतिवादी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद रखता है। दलील केवल इस आशय की है कि प्रतिवादी लाभ का पद धारण करता है।

4. इसलिए, इस मामले में एकमात्र जांच जो आवश्यक है वह चुनाव याचिका को समग्र रूप से पढ़ने पर यह देखना है कि क्या याचिकाकर्ता ने कार्यवाही का कारण बताया है।

निर्विवाद तथ्य

5.प्रतिवादी जब केरल विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तब वह केरल राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था। याचिकाकर्ता ने वास्तव में अनुबंध पी1 (डी) (अनुलग्नक-डी) के अनुसार, उनके नामांकन पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति, जहां तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

> "श्री अब्दुल कादर गुरुवयूर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। वह केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वह केरल सरकार के तहत लाभ का पद संभाल रहे हैं और इसलिए अयोग्य हैं।" (जोर दिया गया)

6. हालाँकि, दिनांक 29.03.2011 के आदेश के अनुसार, आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता बिना किसी संदेह के यह साबित करने में विफल रहा कि क्या वक्फ बोर्ड के निर्वाचित पदाधिकारी लाभ के पद के दायरे में आएंगे जैसा कि अनुच्छेद के तहत कहा गया है। भारत के संविधान की धारा 191 [अनुलग्नक-पी1(सी)-(अनुलग्नक-सी)]।

चुनाव याचिका में दलीलें

7. यह देखने के लिए कि क्या चुनाव याचिका में दिए गए तथ्य कार्रवाई का कारण बनते हैं, हम दिए गए जोर के साथ प्रासंगिक तथ्यों को निकालेंगे। चुनाव याचिका के पैराग्राफ-3 में यह इस प्रकार कहा गया है:

> "3. याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि चुनाव की तारीख पर, पहले प्रतिवादी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उस दिन वह लाभ के पद पर था, अर्थात् केरल राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष। धारा के संदर्भ में 1995 के वक्फ अधिनियम (केंद्रीय अधिनियम 43) के 14(9), राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात् पहले प्रतिवादी को 29 दिसंबर, 2008 को केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
>
> Xxx xxx
>
> "राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वक्फ अधिनियम 1995 के तहत विशेष रूप से वैधानिक प्रकृति के सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वह अर्ध न्यायिक और पर्यवेक्षी शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। उन्हें ऐसा पारिश्रमिक मिलता है जो केरल सरकार द्वारा प्रदान और निर्धारित किया जाता है... "

8. चुनाव याचिका का पैराग्राफ-4 प्रासंगिक सीमा तक इस प्रकार है:

> "4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 191 प्रासंगिक सीमा तक इस प्रकार है:-

"191. सदस्यता की अयोग्यता.-(1) एक व्यक्ति को किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा-

(ए) यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा घोषित पद के अलावा इसके धारक को अयोग्य नहीं ठहराता है;

(बी) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

सी) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(डी) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है;

(ई) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

(स्पष्टीकरण.-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा, केवल इस कारण से कि वह या तो मंत्री है संघ या ऐसे राज्य के लिए.

(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य है।

9.. चुनाव याचिका का पैराग्राफ-5 रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आपत्ति और उसके पारित आदेश को संदर्भित करता है, जिसका उल्लेख हम पहले ही ऊपर कर चुके हैं।

10. चुनाव याचिका का पैराग्राफ-6 इस प्रकार है:

> "6. याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि शीर्ष न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांतों के संदर्भ में, अन्य परीक्षणों के अलावा, निम्नलिखित स्वीकृत तथ्यों के मद्देनजर पहला प्रतिवादी 'लाभ के पद का धारक' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है।
>
> (1) उन्हें केरल राज्य द्वारा एक वैधानिक रूप से गठित निकाय के सदस्यों में से नियुक्त किया गया था।
>
> (2) वह राज्य सरकार द्वारा हटाने योग्य है।
>
> (3) उनके द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए और उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए और उक्त नियुक्ति को राजपत्र में विधिवत अधिसूचित किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया था।
>
> (4) पहले प्रतिवादी को मानद भत्ता, भत्ते और राज्य के खर्च पर कार की सुविधा का आनंद लेने और अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
>
> (5) उनके द्वारा धारित कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है।
>
> (6) सरकार द्वारा नियंत्रण और निर्भरता की एक डिग्री होती है और सरकारी कार्य किए जाते हैं। ·

इसके अलावा, पारिश्रमिक का भुगतान करने से लाभ के पद के धारक, पहले प्रतिवादी द्वारा किए गए कार्यों को उसके कर्तव्यों और कार्यों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के साथ सरकार द्वारा किया जाता है। निःसंदेह उस पद से जिस पर वह पहले स्थान पर हैं प्रतिवादी आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है और उसके पास जो पद है वह स्थायी प्रकृति का है।"

11. चुनाव याचिका के पैराग्राफ-7 में, यह निम्नानुसार निवेदन किया गया है:

"7. पहले प्रतिवादी को कार चालक की सुविधा दी गई है, जिसका वेतन और अन्य भत्ते भी केरल सरकार के कोष से दिए जाते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि वह जिस पद पर है वह 'लाभ का पद' है '...'

12. चुनाव याचिका के पैराग्राफ-10 में, यह इस प्रकार बताया गया है:

"10. चूंकि चुनाव की तारीख पर, पहला प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद संभाल रहा था, इसलिए उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था....

13. संबंधित चुनाव याचिका का ग्राउंड-ए, प्रासंगिक सीमा तक, इस प्रकार है:

"चुनाव की तारीख पर, निर्वाचित उम्मीदवार, पहले प्रतिवादी को धारा 100 (1) (ए) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत लाभ का पद धारण कर रहा था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, माना जाता है कि पहले प्रतिवादी को केरल राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। माना कि वह राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राज्य से वित्तीय अनुलाभ और भत्ते प्राप्त करने और आर्थिक लाभ का आनंद लेने के

हकदार थे और थे। इसलिए, वह थे लाभ का पद धारण करना जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्यता है और अब भी वह इस पद पर बने हुए हैं। इस प्रकार, पहला प्रतिवादी केरल राज्य विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से अयोग्य था।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

14. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 (इसके बाद 'आरपी अधिनियम' के रूप में संदर्भित), इस प्रकार है:

"83. याचिका की सामग्री.-(1) एक चुनाव याचिका-

(ए) उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है;

(बी) याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसे भ्रष्ट आचरण करने वाले कथित पक्षों के नाम और ऐसे प्रत्येक अभ्यास के कमीशन की तारीख और स्थान का यथासंभव पूरा विवरण शामिल होगा; और

(सी) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और दलीलों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा:

[बशर्ते कि जहां याचिकाकर्ता किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, तो याचिका के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा भी संलग्न किया जाएगा यदि ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप का समर्थन और उसका विवरण हो।]

(2) याचिका की किसी भी अनुसूची या अनुलग्नक पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और याचिका के समान तरीके से सत्यापित किए जाएंगे।" (जोर दिया गया)

आरपी अधिनियम की धारा 83(1)(बी) के विपरीत, आरपी अधिनियम की धारा 83(1)(ए) के तहत आवश्यकता यह है कि चुनाव याचिका में केवल भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, न कि भौतिक विवरण। . ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'संक्षिप्त' का अर्थ है, 'संक्षिप्त और व्यापक' संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 'संक्षिप्त' शब्द का अर्थ 'बहुत सारी जानकारी स्पष्ट रूप से और कम शब्दों में देना' दिया है। वेबस्टर कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी, इंटरनेशनल एडिशन के अनुसार, अभिव्यक्ति को 'बहुत संक्षेप में व्यक्त करना' के रूप में परिभाषित किया गया है। तथ्यों को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करने के बाद, क्या यह कहा जा सकता है कि यह भौतिक तथ्यों का कोई संक्षिप्त विवरण नहीं है?

15. भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना अयोग्यता है। यदि चुनाव याचिका को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो वह आधार स्पष्ट है या नहीं, यह उच्च न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर की जाने वाली सरल प्रक्रिया है। सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (ए) के तहत ऐसा करने पर। चुनाव याचिका के पैराग्राफ-3 में, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अर्थात लाभ के पद पर था। फिर से उसी पैराग्राफ में, यह कहा गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसा पारिश्रमिक मिलता है जो केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और निर्धारित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 191 का हवाला देते हुए यह दलील दी गई है कि जो भी व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद रखता है, उसे विधान सभा का चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। यह फिर से दलील दी गई है कि केरल राज्य ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की अयोग्यता को हटाने के लिए कोई कानून

नहीं बनाया है, केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्य हैं। पैराग्राफ-6 में विवरण गिनाते हुए, यह दलील दी गई है कि वह लाभ का पद धारण कर रहा था, उसे मानदेय भत्ते दिए गए थे और वह राज्य के खर्च पर कार की सुविधा का आनंद ले रहा था और अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था। फिर, पैराग्राफ- के तहत, यह कहा गया है कि पहले प्रतिवादी को ड्राइवर प्रदान किया गया था, जिसका वेतन और भत्ते भी केरल सरकार के फंड से दिए जाते हैं। पैराग्राफ-10 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "चूंकि चुनाव की तारीख पर, पहला प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद संभाल रहा था, इसलिए उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था"। चुनाव याचिका में ग्राउंड-ए में, यह दोहराया गया है कि पहले प्रतिवादी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्यता का सामना करना पड़ा क्योंकि वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद संभाल रहा था और वह इसके लिए हकदार था। केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में केरल राज्य से वित्तीय अनुलाभ और भत्ते और आर्थिक लाभ और इसलिए, वह लाभ का पद धारण कर रहे थे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्यता थी। इस प्रकार उन्हें केरल राज्य विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये कथन, हमारे लिए स्पष्ट रूप से कार्रवाई के कारण का खुलासा करते हैं, अर्थात प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद पर था और केरल सरकार से वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहा था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ए) के तहत अयोग्य है, क्योंकि केरल राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना। यह चुनाव याचिका में विचारणीय मुद्दा है।

16. यह प्रश्न कि क्या चुनाव याचिका की अनुसूची या अनुलग्नक चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग है, इस न्यायालय द्वारा पहली बार सहोदराबाई राय बनाम राम सिंह

अहरवार१ में चर्चा की गई थी। यह माना गया कि एक अनुसूची या एक अनुलग्नक जो मामले में केवल एक साक्ष्य है और केवल याचिकाकर्ता को ताकत जोड़ने के लिए शामिल किया गया है, चुनाव याचिका का अभिन्न अंग नहीं बनता है। यह एक ऐसा मामला था जहां आरपी अधिनियम की धारा 83(2) के तहत आवश्यक अनुलग्नकों को चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

17. सहोदराबाई राय मामले (सुप्रा) में उठाया गया प्रश्न था:

> "क्या चुनाव याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81(3)२ के उल्लंघन के लिए खारिज की जा सकती है, क्योंकि याचिका के अनुबंध-ए की प्रति प्रतिवादियों को तामील करने के लिए याचिका के साथ नहीं दी गई थी।"

18. इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा एम कमलम बनाम डॉ. वी. ए. सैयद मोहम्मद३ में फिर से विचार किया गया, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-5 इस प्रकार है:

> "5. अब, पहला प्रश्न जो उठता है वह यह है कि धारा 81 उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए एक चुनाव याचिका का गठन क्या होता है। क्या यह केवल चुनाव याचिका तक ही सीमित है या इसमें एक अनुसूची या अनुलग्नक भी शामिल है जिस पर विचार किया गया है धारा 83 की उप-धारा (2) या धारा 83 उप-धारा (1) के परंतुक में संदर्भित एक सहायक हलफनामा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें धारा 83 की ओर रुख करना होगा जो एक चुनाव याचिका की सामग्री से संबंधित है। उपधारा (1) उस धारा में यह निर्धारित किया गया है कि एक चुनाव याचिका में क्या शामिल होगा और यह प्रावधान किया गया है कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और दलीलों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में

निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा। परंतुक की आवश्यकता है कि जहां याचिकाकर्ता किसी भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, चुनाव याचिका के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा भी संलग्न किया जाएगा। जिस संदर्भ में प्रावधान होता है वह स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि हलफनामे पर विचार किया जाना है चुनाव याचिका के हिस्से के रूप में। अन्यथा इसे चुनाव याचिका की सामग्री से संबंधित अनुभाग में पेश करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसे उप-धारा के प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है जो बताता है कि चुनाव याचिका की सामग्री क्या होगी। उपधारा (2) भी सादृश्य द्वारा इस अनुमान का समर्थन करती है। इसमें प्रावधान है कि चुनाव याचिका की किसी भी अनुसूची या अनुबंध पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और चुनाव याचिका की तरह ही सत्यापित किए जाएंगे। सहोदराबाई राय बनाम राम सिंह अहरवार मामले में इस न्यायालय के फैसले से अब यह स्थापित हो गया है कि उप-धारा (2) केवल एक अनुसूची या अनुबंध पर लागू होती है जो चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग है, न कि एक अनुसूची या अनुलग्नक जो मामले में केवल साक्ष्य है लेकिन जो केवल इसे ताकत जोड़ने के लिए चुनाव याचिका के साथ जोड़ा गया है। उप-धारा (2) के दायरे और दायरे को सहोदराबाई मामले में न्यायालय की ओर से पृष्ठ 19-20 पर बोलते हुए न्यायाधिपति हिदायतुल्ला द्वारा निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया था:

"हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि धारा 83 की उप-धारा (2) में किसी दस्तावेज़ का संदर्भ नहीं है जो कि कथनों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत

किया गया है लेकिन चुनाव याचिका के उन कथनों के लिए जो चुनाव याचिका में नहीं बल्कि संलग्न अनुसूचियों या अनुलग्नकों में रखे गए हैं। हम ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट होगा कि चुनाव याचिका के कई कथन अनुसूचियों या अनुलग्नकों के रूप में रखे जाने योग्य हैं। उदाहरण के लिए, पहले वहां के भ्रष्ट आचरण का विवरण अनुसूचियों में अलग से दिया जाता था और जो कुछ मामलों में वर्तमान कानून में संशोधन के बाद भी किया जा सकता है। इसी प्रकार, का विवरण चुनाव याचिका में शामिल किए जाने के लिए अत्यधिक उपयुक्त कथनों को चुनाव याचिका की अनुसूची या अनुलग्नकों में निर्धारित किया जा सकता है। कानून की आवश्यकता है कि भले ही वे चुनाव याचिका से बाहर हों, उन्हें हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अनुलग्नकों या अनुसूचियों को तब चुनाव याचिका के साथ एकीकृत माना जाता है और सेवा के संबंध में आवश्यकता होने पर उनकी प्रतियां प्रतिवादी को दी जानी चाहिए चुनाव याचिका का पूर्णतः अनुपालन किया जाना है। लेकिन हमने यहां जो कहा है वह उन दस्तावेजों पर लागू नहीं होता है जो मामले में केवल सबूत हैं, लेकिन स्पष्टता के कारणों और याचिका को बल देने के लिए वापस नहीं रखे जाते हैं बल्कि चुनाव याचिकाओं के साथ प्रस्तुत या दायर किए जाते हैं। वे किसी भी तरह से याचिका के कथनों का अभिन्न अंग नहीं हैं, बल्कि केवल उन कथनों के साक्ष्य हैं और उनके सबूत हैं।

इसलिए यह देखा जाएगा कि यदि कोई अनुसूची या अनुलग्नक चुनाव याचिका का अभिन्न अंग है, तो इसे याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और सत्यापित किया जाना चाहिए

क्योंकि यह चुनाव याचिका का हिस्सा है। उप-धारा (2) की विषय-वस्तु इस प्रकार एक अनुसूची या अनुलग्नक है जो चुनाव याचिका का हिस्सा बनती है और इसलिए इसे धारा 83 में रखा गया है जो एक चुनाव याचिका की सामग्री से संबंधित है..." (जोर दिया गया)

19. वर्तमान मामले में चुनाव याचिका से जुड़े सभी अनुबंधों पर चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 83(2) के तहत आवश्यकता के अनुसार हस्ताक्षर और सत्यापन किया गया है, जैसा कि अनुबंध-पी1 (कोली) से देखा जा सकता है। इसलिए चुनाव याचिका का अनुबंध-पी1 (डी) (यहां अनुबंध-0) चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग है। एक स्पष्ट और स्पष्ट दलील है कि प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड का एक पद संभाल रहा था। केरल सरकार के अधीन लाभ अर्जित किया और इसलिए, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

20. अनुबंध-डी को चुनाव याचिका के पैराग्राफ-5 में संदर्भित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"5. फिर भी, पहले प्रतिवादी ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। आपत्ति ली गई कि पहले प्रतिवादी को भारत के संविधान के तहत सीट भरने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था बिना किसी सोच-विचार के। आदेश की एक प्रति इसके साथ प्रस्तुत की गई है और इसे अनुबंध सी के रूप में चिह्नित किया गया है, इसमें दर्शाई गई तारीख को 29.3.2011 के रूप में सही किया गया है, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद इसके साथ प्रस्तुत किया गया है और अनुबंध सी 1 के रूप में चिह्नित किया गया है और आपत्ति

प्रस्तुत की गई है। अग्रेषण पत्र के साथ याचिकाकर्ता को प्रस्तुत किया गया है और उसे अनुबंध डी के रूप में चिह्नित किया गया है।"

21. हाल ही में, जी.एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार'४ (निर्णय हममें से एक, न्यायाधिपति लोकुर, द्वारा लिखा गया है) मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को इस मुद्दे का उल्लेख करने का अवसर मिला। सहोद्राबाई राय मामले (सुप्रा) का जिक्र करते हुए, इसे पैराग्राफ में आयोजित किया गया था-

54 से 56 इस प्रकार है:

"54. सहोदराबाई राय बनाम राम सिंह अहरवार५ में जो प्रश्न उठाया गया वह इस प्रकार था: (एआईआर पृ. 1080, पैरा 3)

"3... 'क्या चुनाव याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 (3) के उल्लंघन के लिए खारिज की जा सकती है क्योंकि याचिका के अनुबंध ए की प्रति याचिका के साथ नहीं दी गई थी। उत्तरदाताओं पर कार्य किया गया।"

55. यह नोट किया गया कि अनुवादित पुस्तिका की सामग्री को चुनाव याचिका में शामिल किया गया था। यह भी नोट किया गया कि चुनाव याचिका की सुनवाई के लिए, जहां तक संभव हो, सीपीसी के प्रावधानों का पालन करना होगा। इसलिए, इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए सीपीसी को देखकर समस्या का सामना किया कि यदि विचाराधीन मामला एक मुकदमा था और चुनाव याचिका का मुकदमा नहीं था तो मामला क्या होता।

56. यह माना गया कि जहां चुनाव याचिका में शामिल किए जाने के लिए प्रकथन बहुत अधिक उपयुक्त हैं, उन्हें चुनाव याचिका की

अनुसूची या अनुलग्नकों में निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, ये अनुसूचियां या अनुलग्नक चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग होंगे और इसलिए, उत्तरदाताओं को दिए जाने चाहिए। यह उन दस्तावेज़ों से बिल्कुल अलग है, जिन्हें साक्ष्य के रूप में चुनाव याचिका के साथ जोड़ा जा सकता है और इसलिए यह चुनाव याचिका के कथनों का अभिन्न अंग नहीं बनते हैं और इसलिए, उत्तरदाताओं पर लागू नहीं किए जा सकते हैं।"

22. इसके अलावा, पैराग्राफ-57 में, एम.कमलम मामले (सुप्रा) का भी संदर्भ है और इसे इस प्रकार माना गया है:

"57.एम. कमलम बनाम वी.ए. सैयद मोहम्मद में इस न्यायालय ने सहोदराबाई राय का अनुसरण किया और माना कि एक अनुसूची या एक अनुबंध जो एक चुनाव याचिका का अभिन्न अंग है, उसे अधिनियम की धारा 83(2) के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। इसी तरह अधिनियम की धारा 83(1) के परंतुक में उल्लिखित हलफनामा जहां चुनाव याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है, वह भी चुनाव याचिका का एक हिस्सा है। यदि चुनाव याचिका के अंत में हलफनामा सत्यापित है एक सच्ची प्रतिलिपि के रूप में, तो आवश्यकता के साथ पर्याप्त अनुपालन होता है अधिनियम की धारा 81(3) और यह चुनाव याचिका को स्वयं प्रमाणित करने के समान होगी।"

23. अगर दलीलों को समग्र रूप से देखा जाए, तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वे भौतिक तथ्यों का गठन करते हैं ताकि एक विचारणीय मुद्दा उठाया जा सके कि क्या पहला प्रतिवादी लाभ का पद धारण करते हुए केरल राज्य विधान सभा में चुनाव लड़ने

के लिए अयोग्य है। राज्य सरकार के अधीन केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में।

24. सवाल यह नहीं है कि क्या केरल राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष लाभ का पद है या नहीं। यही वह मुद्दा है जिस पर प्रयास किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में ऐसा कोई सवाल उठाया है. भारत के संविधान के तहत अयोग्यता, राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना है। याचिकाकर्ता ने उस संबंध में सभी भौतिक विवरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, याचिका कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है।

25. आखिरकार, सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (ए) के तहत जांच केवल इस बात के लिए है कि क्या बताए गए तथ्य कार्रवाई का कारण बताते हैं, न कि कार्रवाई का पूरा कारण। सीमित जांच केवल यह देखने के लिए है कि क्या याचिका को दहलीज पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। एक चुनाव याचिका में, आरपी अधिनियम की धारा 83 के तहत भौतिक तथ्यों का सटीक और संक्षिप्त विवरण प्रदान करना आवश्यक है। अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य' का स्पष्ट अर्थ है विषय वस्तु से संबंधित तथ्य और जिन पर चुनाव याचिका पर भरोसा किया जाता है। यदि पार्टी उन तथ्यों को साबित नहीं करती है तो वह मुकदमे में विफल हो जाता है (देखें फिलिप्स बनाम फिलिप्स और अन्य६; मोहन रावले बनाम दामोदर तात्याबा उपनाम दादासाहब और अन्य७).

26. इस न्यायालय ने अज़हर हुसैन बनाम राजीव गांधी८ के पैराग्राफ-11 में यह माना है कि:

"11...चुनाव याचिका में कोई विशेष तथ्य महत्वपूर्ण है या नहीं और उस पर पैरवी करना आवश्यक है, यह लगाए गए आरोप की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है...।"

लगाया गया आरोप यह है कि प्रतिवादी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद रखता है और उस क्षमता में वह केरल सरकार से उस कार्यालय से जुड़े मुनाफे का आनंद लेता है।

27. वी.एस.च्युतानंदन बनाम पी.जे. फ्रांसिस और अन्य९ तीन न्यायाधीशों की इस अदालत की पीठ ने यह विचार किया है कि केवल इसलिए कि पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है, एक चुनाव याचिकाकर्ता को दहलीज से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद-15 उद्धृत करने के लिए:

"15. ... एक चुनाव याचिका केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि कथित भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण नहीं दिया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि भौतिक तथ्य ऐसे प्राथमिक तथ्य हैं जिन्हें परीक्षण में साबित किया जाना चाहिए किसी पक्ष द्वारा कार्यवाही के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए। चुनाव याचिका में कोई विशेष तथ्य एक भौतिक तथ्य है या नहीं, और इस प्रकार, दलील देना आवश्यक है, यह एक प्रश्न है जो लगाए गए आरोप की प्रकृति, आधार पर निर्भर करता है पर भरोसा किया, और मामले की विशेष परिस्थितियों के आलोक में..."

28. फिर से वी.एस.अचुतानंदन मामले (सुप्रा) के पैराग्राफ -16 में, यह माना गया कि:

"16. ... जब तक दावा कार्यवाही के कुछ कारणों का खुलासा करता है या न्यायाधीश द्वारा निर्णय लेने योग्य कुछ प्रश्न उठाता है, केवल यह

तथ्य कि मामला कमजोर है और सफल होने की संभावना नहीं है, इसे खारिज करने का कोई आधार नहीं है। दलीलों के दायित्व के निहितार्थ को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि यह कार्यवाही का कोई उचित कारण नहीं बताता है, आमतौर पर स्पष्ट रूप से समझे जाने की तुलना में अधिक ज्ञात हैं..."

Xxx xxx

"... कार्यवाही के उचित कारण का खुलासा करने में दलीलों की विफलता पूर्ण विवरण की अनुपस्थिति से अलग है..."

(जोर दिया गया)'

29. हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी१० में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अभिव्यक्ति ' कार्यवाही का कारण' का अर्थ अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए तथ्यों को साबित करना होगा, यदि उनका पता लगाया जाए। और यह कि पार्टी का कार्य ऐसी अतिरिक्त जानकारी के साथ कार्यवाही के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है ताकि विपरीत पक्ष को उस मामले के बारे में समझ आ सके जिससे उसे मिलना होगा। अनुच्छेद-23 को उद्धृत करने के लिए

"23....अभिव्यक्ति " कार्यवाही का कारण" को हर उस तथ्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए वादी के लिए साबित करना आवश्यक होगा। भौतिक तथ्य कार्रवाई के अपूर्ण कारण की ओर ले जाता है और दावे का विवरण ख़राब हो जाता है। पार्टी का कार्य ऐसी अतिरिक्त जानकारी के साथ कार्यवाही के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है ताकि विपरीत पक्ष को मामला समझ में आ सके। मिलना होगा। (सामंत एन. बालकृष्ण बनाम जॉर्ज फर्नांडीज, जीतेंद्र बहादुर सिंह बनाम कृष्ण बिहारी देखें।) केवल मंत्र जाप जैसे अनुभाग

के शब्दों को उद्धृत करना भौतिक तथ्यों को बताने के बराबर नहीं है। भौतिक तथ्यों में सकारात्मक कथन शामिल होंगे यदि आवश्यक हो तो तथ्यों के साथ-साथ नकारात्मक तथ्य का भी सकारात्मक अनुमान। वी.एस. अच्युतानंदन बनाम पी.जे. फ्रांसिस में इस न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला के परिप्रेक्ष्य में माना है कि भौतिक तथ्य ऐसे प्रारंभिक तथ्य हैं जिन्हें साबित किया जाना चाहिए। कार्यवाही के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक पक्ष द्वारा परीक्षण। "भौतिक तथ्यों" को प्रस्तुत करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के बाद ऐसे भौतिक तथ्यों को पेश करने के लिए दलीलों में कोई संशोधन करने की अनुमति नहीं है।

30. सैयद दस्तगीर बनाम टी.आर. में गोपालकृष्ण शेट्टी[11] ने दलीलों का जिक्र करते हुए पैराग्राफ-9 में कहा है कि:

> '9.... किसी भी दलील में दलील का अर्थ लगाते समय, अदालतों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दलील कला और विज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि राहत के लिए किसी के मामले के तथ्य और कानून को शब्दों के माध्यम से रखने की अभिव्यक्ति है। ऐसी अभिव्यक्ति स्पष्ट, सटीक और कभी-कभी अस्पष्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी पूरी दलील पढ़कर ही यह पता लगाया जा सकता है कि वह क्या कहना चाहता है, यह अपील तैयार करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है...।"
>
> "...इसलिए क़ानून के सटीक शब्दों के यांत्रिक उत्पादन पर ज़ोर देना सार के बजाय रूप पर ज़ोर देना है। इसलिए अगर पहले से ही

अनुरोध किया गया हो तो रूप की अनुपस्थिति सार को भंग नहीं कर सकती है।"

31. मेयर (एच.के.) लिमिटेड बनाम मालिक और पक्ष, वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस 12 में, पैराग्राफ -12 में इस न्यायालय ने कहा कि:

"12.... अदालत को यह पता लगाने के लिए संपूर्ण वादपत्र को पढ़ना होगा कि क्या यह कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है और यदि ऐसा होता है, तो संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा वादपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है . अनिवार्य रूप से, क्या वादी कार्यवाही के कारण का खुलासा करता है या नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न है जिसे वादी में किए गए कथनों के आधार पर इकट्ठा किया जाना चाहिए और उन कथनों को पूरी तरह से सही माना जाना चाहिए। कार्यवाही का कारण एक बंडल है राहत प्राप्त करने के लिए जिन तथ्यों को साबित करना आवश्यक है और उक्त उद्देश्य के लिए, भौतिक तथ्यों को बताया जाना आवश्यक है, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर सबूत नहीं, जहां दलीलें गलत बयानी, धोखाधड़ी, जानबूझकर डिफ़ॉल्ट के संबंध में हैं। अनुचित प्रभाव या उसी प्रकृति का। जब तक वादी कार्यवाही के कुछ कारण का खुलासा करता है जिसके लिए अदालत द्वारा निर्धारण की आवश्यकता होती है, केवल यह तथ्य कि न्यायाधीश की राय में वादी सफल नहीं हो सकता है, वादी को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।"

32. पोन्नाला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और अन्य१३ के हालिया फैसले में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ -17 और 29 में कहा था कि:

"17.... अदालतों को याचिकाओं को खारिज करने के अनुरोधों से निपटने में सतर्क रहने की जरूरत है और केवल उन मामलों में खारिज करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जहां याचिका को पढ़ने पर भी कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है।"

(जोर दिया गया)

Xxx xxx

"29.... एक चुनाव जो अधिनियम की धारा 100 और 123 में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण, अवैधताओं और अनियमितताओं के कारण दूषित होता है, उसे स्पष्ट रूप से मतदाताओं के बहुमत के निर्णय के रूप में मान्यता और सम्मान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, अदालतें हैं , जब भी आरोप लगाए जाते हैं तो कानून के ढांचे के भीतर अपने दृष्टिकोण में अनावश्यक रूप से अतितकनीकी हुए बिना और जमीनी हकीकत से बेखबर हुए बिना उसकी जांच करना कर्तव्य है।"

33. अंत में, जैसा कि राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरूगांधी और अन्य१४ में इस न्यायालय द्वारा चेतावनी दी गई थी, यह माना गया कि:

"19. अभिवचन के नियमों का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई और उचित निर्णय तक पहुंचने में सहायता करना है। कानून की कार्रवाई को शतरंज के खेल के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। कानून के प्रावधान केवल अनुष्ठान के रूप में पालन किए जाने वाले सूत्र नहीं हैं। नीचे कानून के प्रावधान के शब्द। आम तौर पर कहें तो, एक न्यायिक

सिद्धांत निहित है। उस सिद्धांत को सुनिश्चित करना और उसे लागू करना अदालत का कर्तव्य है। ..." (जोर दिया गया)

34. ऊपर उल्लिखित कानून के स्थापित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, हमारा विचार है कि चुनाव याचिका में कार्यवाही के कारण का खुलासा किया गया है, लेकिन इसे सीमा से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए आक्षेपित आदेश और निर्णय को रद्द किया जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। चुनाव याचिका कानून के अनुसार सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को भेजी जाती है।

35. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

राजेंद्र प्रसाद

अपील स्वीकार की गई।

---

१. एआईआर 1968 एससी 1079।

२ 81. याचिकाकर्ता की प्रस्तुति.-XXX (3) प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उसकी उतनी प्रतियां संलग्न की जाएंगी जितनी याचिका में उल्लिखित उत्तरदाताओं की हैं और ऐसी प्रत्येक प्रति को याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत सत्यापित किया जाएगा कि यह सही है याचिका।

३ (1978) 2 एसईसी 659

४. (2013) 4 एसईसी 776

५ एआईआर 1996 एससी 1079

६ (1878) 4 क्यूबीडी 127, 133

७ (1994) 2 एसईसी 392, 399

८ 1986 सप्प एस ईसी 315

९ (1999) 3 एसईसी 737

१० (2001) 8 एसईसी 233

११(1999) 6 एसईसी 337

१२ (2006) 3 एसईसी 100

१३(2012) 1 एसईसी 788।

१४ (1972) 3 एसईसी 850।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।